eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

# भारत में उच्च शिक्षा का विकास–नीतियाँ, सुधार व प्रभाव

**शिवशंकर[1] एवं प्रो.स्वाति सक्सेना[2]**
[1]शोधार्थी, सी.एस.जे.एम.वि.वि. कानपुर
[2]प्रभारी–शिक्षाशास्त्र विभाग, डी0जी0 पी0जी0 कालेज, कानपुर

Received: 20 July 2025 Accepted & Reviewed: 25 July 2025, Published: 31 July 2025

## Abstract

भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में समय के साथ अनेक परिवर्तनों और सुधारों से गुजरी है। आज यह प्रणाली विभिन्न विषयों, शोध, नवाचार और डिजिटल शिक्षा को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार ने उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और रोजगारपरक बनाने के लिए विभिन्न नीतिगत सुधार लागू किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पारम्परिक शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास किया है जिसमें बहुविषयक शिक्षा, शोध को बढ़ावा, डिजिटल शिक्षा, स्वायत्तता और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी गयी है। इन सुधारों का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक और व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना, शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करना और वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के लिए विभिन्न नीतिगत सुधार लागू किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पारम्परिक शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास किया है जिसमें बहु विषयक शिक्षा, शोध को बढ़ावा, डिजिटल शिक्षा, स्वायत्तता और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्राथमिकता दी गयी है। इन सुधारों का उद्देश्य छात्रों को आधुनिक और व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करना, शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करना और वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा प्रणाली की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। हालांकि, उच्च शिक्षा प्रणाली अभी भी वित्तीय संसाधनों की कमी, गुणवत्ता में असमानता और शिक्षण विधियों में सुधार की चुनौतियों का सामना कर रही है। यह शोध पत्र उच्च शिक्षा के विकास में आई प्रमुख नीतियों, उनके प्रभावों और आगे की संभावनाओं का विस्तृत विश्लेषण करता है।

भारत में उच्च शिक्षा तृतीयक स्तर की शिक्षा को संदर्भित करती है जो 12 साल की स्कूली शिक्षा (10 साल प्राथमिक और 2 साल माध्यमिक) के बाद प्राप्त की जाती है। भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है, जिसमें 1000+ विश्वविद्यालय और 42,000+ कॉलेज शामिल हैं।

**प्रमुख शब्द**– उच्च शिक्षा, नवाचार, डिजिटल शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा।

## Introduction

भारत में शिक्षा इसकी उस प्राचीन दार्शनिक परंपरा में गहराई से अंतर्निहित है जहाँ विद्या को महज ज्ञान के संचय के रूप में नहीं बल्कि समग्र आत्म–सशक्तीकरण के साधन के रूप में देखा जाता था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि **''ज्ञान की संपदा वास्तव में सभी प्रकार की संपदाओं में सर्वोच्च है।''** वर्षों से भारत ने ज्ञान की इस अमूल्य संपदा को समृद्ध करने और इसे अपने युवाओं तक पहुँचाने का प्रयास किया है। विशेष रूप से पिछले दशक में, भारत ने वैश्विक रैंकिंग में अपने प्रतिनिधित्व में 18 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है जो कि जी–20 देशों के बीच सबसे अधिक वृद्धि है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस सकारात्मक छलांग पर प्रकाश डालना अहम है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में सार्वजनिक और निजी दोनों विश्वविद्यालय शामिल हैं। सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समर्थन दिया जाता है, जबकि निजी विश्वविद्यालयों को ज्यादातर विभिन्न निकायों और समाजों द्वारा समर्थन दिया जाता है। भारत में विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 से अपनी शक्ति द्वारा प्राप्त करता है। मुख्य शासकीय निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है जो अपने मानकों को लागू करता है, सरकार को सलाह देता है और केन्द्र और राज्य के बीच समन्वय में मदद करता है।[1] उच्च शिक्षा के लिए मान्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा स्थापित विभिन्न स्वायत्त संस्थानों द्वारा देखरेख की जाती है।

2020 तक भारत में 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं जिनमें 54 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 416 राज्य विश्वविद्यालय, 125 डीम्ड विश्वविद्यालय, 361 राज्य निजी विश्वविद्यालय और 159 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं जिनमें एम्स, आईआईएम, आईआईआईटी, आईआईएसईआर, आईआईटी और एनआईटी शामिल हैं।

अन्य संस्थानों में सरकारी डिग्री कॉलेज, निजी कॉलेज, स्वायत्त संस्थान और स्नातकोत्तर अनुसंधान संस्थान के रूप में 52627 कॉलेज शामिल हैं, जो इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कार्यरत हैं, जैसा कि एमएचआरडी ने 2020 में रिपोर्ट किया है। इन संस्थानों के अलावा, कई समानांतर, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त निकाय हैं जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ग्रामीण कौशल विकास मिशन, उन्नत कम्प्यूटिंग के विकास केन्द्र आदि जैसे पेशेवर और व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करते हैं। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली की दूरस्थ शिक्षा और खुली शिक्षा की देखरेख दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा की जाती है। कॉलेज स्वायत्त हो सकते हैं, यानि कुछ मामलों में पीएचडी स्तर तक अपनी डिग्री की जाँच करने के लिए सशक्त हो सकते हैं, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) देश का सबसे पुराना दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय है, जो पत्राचार से ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की ओर अग्रसर है और इसमें सबसे अधिक छात्र नामांकित हैं।

भारत में विश्वविद्यालय अलग–अलग धाराओं में विकसित हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक धारा की निगरानी एक शीर्ष निकाय द्वारा की जाती है, जिसे अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किया जाता है और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है। अधिकांश विश्वविद्यालयों का प्रशासन राज्यों द्वारा किया जाता है, हालांकि 18 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय हैं जिन्हें केन्द्रीय विश्वविद्यालय कहा जाता है, जिनका रखरखाव केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए बढ़ा हुआ वित्त पोषण उन्हें अपने राज्य प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त देता है।

भारत उन देशों में से एक है जिनके पास दुनिया में सदियों पुरानी प्रणालीगत शिक्षा के ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, हालांकि विदेशी शक्तियों, सत्ता–लोलुप शासनों और उपनिवेशवाद के हमले के तहत इसे कई बार विनाश, हेरफेर और पुनर्निर्माण का सामना करना पड़ा है। इसके दुष्परिणामों के बावजूद यह उन चुस्त प्रणालियों में से एक है जिसने स्वविस्तार मूल्यों और सामाजिक–सांस्कृतिक लचीलेपन के कारण राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे परिवर्तनकारी कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर नवाचार करने की क्षमता दिखाई है।

**तृतीयक स्तर की शिक्षा :**

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

भारत में उच्च शिक्षा को 12 साल की स्कूली शिक्षा के बाद प्राप्त की जाने वाली शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है।

**विश्वविद्यालय और कॉलेज**

भारत में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विभिन्न प्रकार के संस्थान मौजूद हैं जिनमें विश्वविद्यालय और कॉलेज शामिल हैं।

**उच्च शिक्षा प्रणाली :**

भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है जिसमें विभिन्न प्रकार के संस्थान, छात्र और शिक्षक शामिल हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय आधुनिक भारत का पहला बहु–विषयक विश्वविद्यालय था। 10 नवम्बर 2005 को दुनिया के शीर्ष कला और मानविकी विश्वविद्यालयों के टाइम्स हायर एजुकेशन सप्लीमेंट के सर्वेक्षण के अनुसार, 39वें स्थान पर यह विश्वविद्यालय उस वर्ष शीर्ष फिजिक्स, एशियाटिक सोसाइटी और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान है।

**उच्च शिक्षा का विकास :**

भारत की शिक्षा प्रणाली दुनिया में सबसे मजबूत और सबसे प्रभावी है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के नाते भारत अभी भी छात्रों के लिए बेहतरीन शिक्षा सुविधायें प्रदान करता है। देश में कई विश्वविद्यालय स्थापित हैं जो विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों को अवसर प्रदान करते हैं। बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय और स्कूल अंतरराष्ट्रीय छात्रों को भी सुविधायें प्रदान करते हैं जो परिसर की संस्कृति को और अधिक विविध और समृद्ध बनाता है। भारत में हर स्तर पर शिक्षा आसानी से उपलब्ध है जो इसे जनता के उपयोग के लिए एक बेहतरीन संसाधन बनाती है और विशेष रूप से भारतीय सरकार शिक्षा के महत्व के बारे में जनता तक पहुँचाने और उन्हें युवा पीढ़ी को इस तरह से शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है कि वे देश और खुद के लिए एक सम्पत्ति बन सकें।

**स्वतंत्रता पूर्व काल :**

1857 में, ब्रिटिश सरकार ने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना करके भारत में यूरोपीय उच्च शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की।

**स्वतंत्रता के बाद :**

स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में काफी विस्तार हुआ और विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की संख्या में वृद्धि हुई।

**नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 :**

भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP-2020) लागू की, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार करना और इसे अधिक समावेशी बनाना है।

**उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान :**

- **भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी)–** यह विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

संस्थान है।

- **भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)–** यह विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक अन्य प्रमुख संस्थान है।
- **अन्य विश्वविद्यालय और कॉलेज–** भारत में कई विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं जो विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर के पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

## उच्च शिक्षा में चुनौतियाँ :

भारत में उच्च शिक्षा कई चुनौतियों से जूझ रही है, जिनमें असमान पहुँच, सीमित वित्तपोषण, संकाय की कमी, और उद्योग अकादमिक सहयोग का अभाव शामिल है। इन चुनौतियों के कारण शिक्षा की गुणवत्ता, प्रवेश प्रक्रिया और रोजगारपरक कौशल में भी समस्याएँ देखी जा सकती हैं।

- **सकल नामांकन अनुपात (GIR)**–उच्च शिक्षा में भारत का सकल नामांकन अनुपात कम है जो असमान अभिगम को दर्शाता है। खासकर सीमांत समूहों और ग्रामीण आबादी के लिए।
- **सामर्थ्य–** उच्च शिक्षा तक पहुँच कई छात्रों के लिए मँहगी हो सकती है जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है।
- **रोजगार संबंधी समस्यायें–** उच्च शिक्षा प्राप्त होने के बाद भी छात्रों को रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।
- **संसाधनों की कमी–** विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं और संसाधनों की कमी है।
- **प्रवेश प्रक्रिया–** प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और कुछ संस्थानों में जातिगत आरक्षण के कारण योग्यता आधारित प्रवेश कम हो जाता है।
- **बुनियादी अवसरंचना में अंतराल–** कई क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की बुनियादी अवसरंचना का अभाव है।
- **लैंगिक असमानता–** महिलाओं को उच्च शिक्षा तक पहुँचने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

## भारतीय उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति :

भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति अवसरों और चुनौतियों दोनों से भरी हुई है। भारत की केन्द्र सरकार बेहतर सुविधाओं के लिए सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को वित्त पोषण प्रदान करती है और उन्हें किसी भी तरह की वित्तीय पृष्ठभूमि वाले छात्रों के लिए अधिक सुलभ बनाती है। एक ओर, भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली तेजी से बढ़ रही है जिसमें कई विश्वविद्यालय और कॉलेज कई तरह के कार्यक्रम पेश करते हैं। इसने छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के कई अवसर पैदा किए हैं।

हालांकि भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। मुख्य चुनौतियों में से एक है गुणवत्तापूर्ण संकाय की कमी और शोध एवं विकास के लिए अपर्याप्त निधि। भारत में कई विश्वविद्यालय और कॉलेज बुनियादी ढाँचे और संसाधनों की कमी का भी सामना करते हैं, जो छात्रों को उच्च गुणवत्ता

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

वाली शिक्षा प्रदान करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।

हाल के वर्षों में, भारत सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें शोध और विकास के लिए धन बढ़ाना और उच्च शिक्षा के लिए संस्थानों की स्थापना को बढ़ावा देना शामिल है। यूजीसी ने भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और जवाबदेही में सुधार के लिए कई सुधार भी लागू किए हैं।

इन प्रयासों के बावजूद, भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता कई लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है कि सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का अनुभव प्राप्त हो।

**भारत में उच्च शिक्षा में सुधार के लिए सिफारिशें :**

भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली में सुधार एक जटिल और बहुआयामी चुनौती है जिसके लिए सरकार, शिक्षकों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र सहित कई हितधारकों की भागीदारी और सहयोग की आवश्यकता है। कुछ संभावित सिफारिशें इस प्रकार हैं–

**शिक्षा के लिए सरकारी निधि में वृद्धि–** सरकार को शिक्षा, विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए अधिक निधि आवंटित करनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि विश्वविद्यालयों के पास छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो।

1. **शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार–** सरकार को शिक्षकों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हैं। शिक्षकों को व्यावसायिक विकास के अवसर और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके ऐसा किया जा सकता है।
2. **अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना–** सरकार को अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण और सहायता प्रदान करके तथा विश्वविद्यालयों, शोधकर्ताओं और निजी क्षेत्र की कम्पनियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करके उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए।
3. **शिक्षा तक पहुँच बढ़ाना–** सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी छात्रों को निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए वित्तीय सहायता, छात्रवृत्ति और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच हो।
4. **जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करें–** सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विश्वविद्यालय अपने कार्यों में जवाबदेह और पारदर्शी हों।

भारत में उच्च शिक्षा को सशक्त करने के लिए कई उपाए किए जा सकते हैं जैसे कि उद्योग अकादमिक एकीकरण को बढ़ावा देना, शैक्षणिक परिवर्तन करना, गुणवत्ता आश्वासन सुधार करना, छात्र सहायता और विकास के लिए बेहतर व्यवस्था करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना, क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना, कौशल विकास को बढ़ावा देना, और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को बढ़ावा देना।

- **उद्योग–अकादमिक एकीकरण**–उद्योग अकादमिक एकीकरण के लिए संकाय सदस्यों के लिए अनिवार्य उद्योग अवकाश की व्यवस्था की जा सकती है और उद्योग विशिष्ट पाठ्यक्रम सलाहकार बोर्ड की

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

स्थापना की जा सकती है।

- **शैक्षणिक परिवर्तन–** सभी संकाय सदस्यों के लिए शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रमाणन लागू किया जा सकता है, और शिक्षण उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जा सकते हैं।
- **गुणवत्ता आश्वासन–** सतत् मूल्यांकन प्रणाली को लागू किया जा सकता है और वास्तविक समय गुणवत्ता निगरानी की जा सकती है।
- **छात्र सहायता और विकास–** अनिवार्य कैरियर विकास प्रकोष्ठों की स्थापना की जा सकती है और पेशवर परामर्शदाता और उद्योग संपर्क प्रदान किए जा सकते हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग–**प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ संयुक्त डिग्री कार्यक्रम स्थापित किए जा सकते हैं।
- **क्षेत्रीय भाषा एकीकरण–** क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री विकसित की जा सकती है।
- **कौशल विकास–** उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप मॉड्यूलर कौशल प्रमाणन कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं।
- **राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी–**राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी को बढ़ावा दिया जा सकता है और खुले शैक्षिक संसाधनों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

**अन्य महत्वपूर्ण उपाय :**

- परियोजना आधारित शिक्षा, इंटर्नशिप और उद्योग सहयोग के माध्यम से व्यावहारिक कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जा सकता है।
- नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों को सामाजिक विकास परियोजनाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- उद्यमिता और नवाचार केन्द्र स्थापित किए जा सकते हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ अंतरराष्ट्रीय शिक्षा साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- दोहरे अध्ययन कार्यक्रम लागू किए जा सकते हैं।
- ब्लॉकचेन प्रमाण पत्रों के साथ योग्यता आधारित प्रमाणन प्रणाली अपनाई जा सकती है।

**निष्कर्ष :**

भारत में उच्च शिक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि इस क्षेत्र में कई चुनौतियाँ भी हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में भारत सरकार और अन्य हितधारकों की भूमिका महत्वपूर्ण हैं। सरकार भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश के संबंध में विभिन्न कदम

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 04, Issue 07, July 2025

उठा रही है।

सरकार भारतीय विश्वविद्यालयों में बुनियादी ढांचे, संकाय और अनुसंधान के विकास में निवेश कर रही है। इसके अतिरिक्त, इसने उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतियों और योजनाओं को लागू किया है जैसे कि उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेन्सी (HEFA) और राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF)।

गैर लाभकारी संगठन, निगम और परोपकारी संगठन जैसे हितधारक भी भारत में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अनुसंधान, छात्रवृत्ति और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए धन मुहैय्या कराते हैं और छात्रों की रोजगार क्षमता में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच साझेदारी स्थापित करने में भी मदद करते हैं।

इसके अलावा, भारत में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने में निजी संस्थानों और विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, अत्याधुनिक सुविधायें प्रदान करते हैं, और छात्रों को विश्वस्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करते हैं।

निष्कर्ष रूप में, भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश के संबंध में इस कदम के फायदे और नुकसान दोनों हैं। इसमें नए शैक्षणिक दृष्टिकोण, उन्नत प्रौद्योगिकी और शोध के अवसर लाने की क्षमता है, जिससे भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में समग्र सुधार होगा। अंततः ध्यान एक गतिशील और समावेशी शिक्षा प्रणाली बनाने पर होना चाहिए जो छात्रों, संस्थानों और व्यापक समाज को लाभान्वित करे।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. एन0ई0पी0–2020 : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
2. उच्च शिक्षा विकास एवं चुनौतियां
3. शर्मा, ओ.पी. (2013–14) शिक्षा के दार्शनिक आधार
4. पाटनी,मंजू एवं हरपालानी, (2023–2024) : प्रसार षिक्षा एवं संचार
5. सोनी, अनिल (2021) वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली व वर्तमान शिक्षक शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन, NJRIP
6. International Journal of Education and Management, PPH Publishing Corporation.
7- Zeichner, K. (2012). *Teacher education and the politics of race and class*. Journal of Teacher Education, 63(3), 213-227.
8- Harris, J., & O'Rourke, D. (2018). *Competency-based teacher education: A framework for the 21st century*. Teacher Education Quarterly, 45(2), 43-58.
9- Darling-Hammond, L. (2006). *The right to learn: A blueprint for creating schools that work*. Jossey-Bass.
10. www.shodhganga.com